lore, has kindled interest with the handloom weavers all over the country (as reported in the Economic Tiir.es 5th April, 1993);

(b) whether it is a fact that as claimed by the designer, the mecha nised Charkha, is more output orien ted End capable of producing finer
* counts of yarn, more acceptable to the handloom industry which is now solely dependent on the mill made yarn; and

(c) if so, whether Government would give adequate encouragement to Me hanised Charkha in rural sec tor to take up the mighty mill made yarn industry?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) (a) and (b) Government has riot received any such report from the handloom agencies or weavers.

(c) Does not arise.

Enquiry in H.HE.C.

1697. DR. NARREDDY THULASI REDDY; Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a fact finding enquiry has been ordered into the ac+ivities of the top management of HHEC.

» (b) if so. whether it is also a fact that the Textile Commi-cioner conducted such an enquiry;

(c) whether his Ministry is delaying action on the findings of this enquiry report;

(d) whether it is fact that some officers are being shielded; and

(e) what stens are being taken to cleanse the too management involved in various dubious deals and transactions

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF, TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) No, Sir.

(e) Does not arise at present.

Assessment of H.H.E.C.

1698. SHRI MENTAY PADMANA-BHAM; Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether any assessment has been made of the performance of the HHEC regarding its profitability, exports and general image;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what is the system presently operating in HHEC to guide the management and also maintain strict supervisory role; and

(d) what are the details of such supervision to ensure probity in the dealings?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) (a) and ,(b) Yes, Sir. Periodical review meetings are held under the Chairmanship of Seretary (Textiles). Last review meeting was held on 15-9-1992.

(c) and (d) The Board of Directors constituted by the Government guides the management and also maintains a supervisory role. This is in addition to the Periodic performance review meetings held under the Charman-shio of Secretary (Textiles). Also, the accounts of the Corporation are audited bv the Comptroller and Auditor General of India.

मध्य प्रदेश में रुकण कपड़ा मिलें

1699. **डा० जिनेन्द्र कमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने, मध्य

प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन संचालित कपड़ा मिलों को रुग्ण घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी मिलें हैं और मध्य प्रदेश में वे कहां-कहां स्थित हैं और मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार उनमें मिल-वार कितने-कितने कर्मकार नियोजित थे;

(ग) क्या सरकार ने, ऐसी मिलों में कार्यरत कर्मकारों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए अब तक कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इन कर्मकारों के भविष्य के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(च) क्या सरकार ऐसी मिलों को बंद करने का निर्णय लेने से पहले, उन्हें चलाने के लिए श्रमिक सहकारी समिति या निजी क्षेत्र या संयुक्त निजी-श्रमिक व्यवस्था कायम करने पर भी विचार करेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने दिनांक 6 अप्रैल, 1993 की अपनी सुनवाई में एन टी सी (एम पी) लि० इंदौर को रुग्ण घोषित किया था और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) को प्रचालनात्मक अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है। आई डी बी आई को कहा गया है कि वह एन टी सी (एम पी) के अन्तर्गत की मिलों के लिये 90 दिनों के भीतर पुनर्वासन योजना को अन्तिम रूप दे। 31-3-93 के अनुसार एन टी सी (एम पी) के अन्तर्गत मिलों की संख्या उनकी अवस्थिति और कामगारों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) से (ङ) सरकार ने एन टी सी मिलों के लिये एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एन टी सी मिल से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर जाने वाले कामगारों के पुनः प्रशिक्षण और पुनः नियोजन के लिये 50 करोड़ रु० से पुनर्वासन निधि के सृजन की परिकल्पना में गई है स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वाले कामगारों के लिये पुनर्वासन योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है और उनको क्रियान्वित किया जा रहा है।

(च) सरकार एन टी सी मिलों के सहकारीकरण के किसी भी अर्थक्षम प्रस्ताव को समर्थन देने के लिये तैयार है बशर्ते कि इस पर सभी सम्बद्ध पक्षों की सहमति हो। तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई भी ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। एन टी सी की अलग-अलग मिलों को बन्द करने या बनाए रखने के मामले पर विचार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना और अन्य तर्कसंगत कारकों का उनकी अर्थक्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के पश्चात किया जाएगा।

विवरण

एन० टी० सी० के अन्तर्गत 31-3-1993 के अनुसार मिलों की संख्या अवस्थिति और कामगारों की संख्या

क्रम सं०	मिल का नाम	अवस्थित	कामगारों की संख्या
1.	इंदौर माल्वा यूनाइटेड मिल्स	इन्दौर	3071
2.	कल्याणमल मिल्स	इन्दौर	2275

1	2	3	4
3.	स्वदेशी टैक्सटाइल मिल्स	इन्दौर	1132
4.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	बुरहानपुर	768
5.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स	राजनन्दगांव	2118
6.	न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल्स	भोपाल	1126
7.	हीरा मिल्स	उज्जैन	1862
			12352

Closure of Jiyajee Cotton Mills

1700. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Jiyajee Cotton Mills, Gwalior (Madhya Pradesh) is under illegal closure since more than 9 months rendering thousands of workers and their families without means of livelihood;

(b) whether it is a fact that no permission was granted by Government to close down the factory;

(c) if so, whether any action was taken against the Management of the Mill for their illegal action;

(d) whether it is also a fact that some workers and members of their family had committed suicide due to penury;

(e) whether Central Government are taking steps to reopen the mill; and

(f) if so, what are the details there of?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) (a) to (d) Jiyajeerao Cotton Mills Ltd., Gwalior, with 6746 workers on the roll; is reportedly closed since 28th April, 1992, mainly due to non-payment of electricity bills to the Madhya Pradesh State Electricity Board. As ascertained, no permission was granted by State Government to"~close down the factory. It is gathered that the State Government has already initiated action against the unit for their defaults in the concerned Courts. The Government is not aware of some workers and members of their families having committed suicide due to penury.

(e) and (f) The case of the mill is registered with Board of Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) for its revival.

12.00 Noon

STATEMENT BY MINISTER

Correcting the reply given in the Rajya Sabha on the 2nd March, 1993 to Unstarred Question 857 regarding theft of parcels from G.P.O., Jaipur